

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2009

विषय:-ग्राम पुरेडा, तहसील गरुड जिला बागेश्वर में 25 नाली भूमि, नव सृजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन न्यायालय) हेतु न्याय विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-771/ग्यारह-एल0ए0सी0/2006-2007 दिनांक-30.05.2009, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल ग्राम पुरेडा, तहसील गरुड, जिला बागेश्वर में गैर ज0वी0ख0 खाता संख्या-60 के पैमाइशी खेत संख्या-3059 मध्ये रकबा 25 नाली भूमि, जो वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की है एवं श्रेणी 9(3) ड की है, को आपके द्वारा की गयी संस्तुति एवं वित्त अनुभाग-3 के शारणादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अन्तर्गत न्याय विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8- प्रस्तावित भूमि पर कोई भी गैर वानिकी कार्य किये जाने से पूर्व वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।
कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

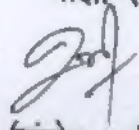
भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0संख्या-117 / समदिनांकित / 2009

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव, न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन।
 - 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 3- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
 - 5- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय।
 - 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
 - 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।